पत्र नहीं मित्र
देशबन्धु
.नई दिल्ली, शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2020 | वर्ष-13 | अंक -238 | पृष्ठ - 10 | मूल्य - 4.00 रुपए

नोएडा एयरपोर्ट के लिए पांच रनवे बनाने की शासन से मिली हरी झंडी

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नोएडा एयरपोर्ट के लिए गठित पीएमआईसी-प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इम्प्लमेंटेशन कमेटी की हुई बैठक
- पांच रनवे के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए मंत्री परिषद ने दी संस्तुति

ग्रेटर नोएडा, 3 दिसम्बर (देशबन्धु)। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जेवर एयरपोर्ट के लिए गठित पीएमआईसी-प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इम्प्लमेंटेशन कमेटी की बैठक गुरुवार लखनऊ लोकभवन में हुई, जिसमें जेवर एयरपोर्ट के दो रनवे को बढ़ाकर 4 से 6 रनवे किए जाने के सम्बन्ध में तकनीकी परामर्शदाता के अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में दो रनवे के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विकास के लिए ग्लोबल ई-बिडिंग में माध्यम से विकासकर्ता के रूप में ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी का चयन किया जा चुका है तथा विगत 07 अक्टूबर को कन्शेसन एग्रिमेंट ज्यूरिख एयरपोर्ट और राज्य सरकार की कम्पनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड-नायल के मध्य हस्ताक्षरित हो चुका है।

मुख्य सचिव के समक्ष परामर्शदाता संस्था पीडब्ल्यूसी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियाल और यमुना प्राधिकरण डॉ. अरुण वीर सिंह ने प्रस्तुतीकरण किया। इस प्रस्तुतीकरण में कुल 05 रनवे की फीजिबिलिटी बतायी गई। वर्तमान में दो रनवे के अतिरिक्त 3 और रनवे बनाए जा सकते है। गहन विचार-विमर्श के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता की पीएमआईसी ने 5 रन वे बनाए जाने तथा वित्त की उपलब्धता होने पर भूमि अधिग्रहण करने की संस्तुति मंत्रिपरिषद के लिए कर दी।

प्रथम चरण में तीसरे रनवे के लिए 1365 हेक्टयर भूमि का अधिग्रहण होगा। प्रथम चरण के दो रन वे के लिए 1334 हेक्टयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। दूसरे चरण में तीन रन वे हेतु कुल 3418 हेक्टयर और भूमि की जरूरत होगी।

दूसरे चरण के प्रथम फेज में 1365 हेक्टेयर, दूसरे फेज में 1318 हेक्टेयर और तीसरे फेज में 735 हेक्टेयर की भूमि सम्मलित होगी। पांच रन वे का जेवर एयरपोर्ट में कुल 4752 हेक्टयर की भूमि सम्मलित होगी।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एवं नागरिक उड्डयन एसपी गोयल ने भी जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता बताई।

बैठक में प्रमुख सचिव न्याय जेपीसिंह, विशेष सचिव मुख्यमंत्री एवं नागरिक उड्डयन सुरेंद्र सिंह और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, सीईओ नोएडा प्राधिकरण रितु माहेश्वरी, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नरेन्द्र भूषण एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।